वैश्विक व्यापार 3% गिरेगा

इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की कार्यकारी निदेशक ने जताई आशंका

■ **संयुक्त राष्ट्र, एजेंसियां.** संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अर्थशास्त्री ने कहा है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क के कारण वैश्विक व्यापार में 3 प्रतिशत की कमी आ सकती है और निर्यात अमेरिका और चीन जैसे बाजारों से भारत, कनाडा और ब्राजील की ओर स्थानांतरित हो सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह एक व्यापक शुल्क योजना की घोषणा की. अमेरिका ने बाद में चीन को छोड़कर अधिकांश देशों के लिए 'जवाबी शुल्क' पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की. बदले में चीन ने अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर 125 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला किया है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र की कार्यकारी निदेशक पामेला कोक-हैमिल्टन ने शुक्रवार को जिनेवा में कहा कि व्यापार तरीके और आर्थिक एकीकरण में महत्वपूर्ण दीर्घकालिक बदलावों के साथ वैश्विक व्यापार में तीन प्रतिशत की कमी आ सकती है. उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए, मेक्सिको से निर्यात, जो अत्यधिक प्रभावित हुआ है, अमेरिका, चीन, यूरोप और यहां तक कि अन्य लातिन अमेरिकी देशों जैसे बाजारों से स्थानांतरित हो रहा है. इससे निर्यात कनाडा और ब्राजील और कुछ हद तक भारत में मामूली लाभ हो रहा है. उन्होंने कहा कि इसी प्रकार वियतनामी निर्यात अमेरिका, मैक्सिको और चीन से हट रहा है, जबकि पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) बाजारों, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और अन्य बाजारों की ओर काफी बढ़ रहा है. परिधान का उदाहरण देते हुए कोक-हैमिल्टन ने कहा कि विकासशील देशों के लिए आर्थिक गतिविधि और रोजगार के मामले में कपड़ा उद्योग शीर्ष उद्योग है. इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर यह लागू होता है तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े परिधान निर्यातक बांग्लादेश को 37 प्रतिशत का जवाबी शुल्क झेलना पड़ेगा, जिससे 2029 तक अमेरिका को वार्षिक निर्यात में 3.3 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है.

उसने शायद यह संकेत देते हुए कि यह भी स्वीकार किया है कि वह शुल्क के साथ जवाबी कार्रवाई करने के अंतिम बिंदु पर पहुंच गया है कि उसके पास अपने शस्त्रागार में बहुत सारे अन्य उपकरण हैं जिन्हें आगे सक्रिय किया जा सकता है यदि अमेरिका आज अतिरिक्त उपायों के साथ जवाब देता है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में लागू भारी शुल्क अमेरिका में चीनी आयात पर 145 प्रतिशत तथा चीन में अमेरिकी आयात पर 125 प्रतिशत - वस्तुतः विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सभी वस्तु व्यापार को रोक देगा.

अमेरिका पर खत्म होते जा रहा विश्वास

अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर ने ग्लोबल स्तर पर निवेशकों और व्यापारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है. भारी उतार-चढ़ाव के कारण निवेशक शेयर बाजार से लेकर बॉन्ड मार्केट तक खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं. टैरिफ वॉर के बीच निवेशक अमेरिकी सरकार के बॉन्ड बेच रहे हैं. आमतौर पर निवेशक ऐसे मौके पर खरीदारी करने के बारे में सोचते हैं या फिर ज्यादा पैसे जुटाकर सही मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन अब वे अमेरिकी बॉन्ड को तेजी से बेच रहे हैं. निवेशकों को हाई रिटर्न का लालच भी नहीं आकर्षित कर पा रहा है. इस घटना को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बड़े ही चिंता का विषय है.

लड़नी है लंबी लड़ाई

यह दर्शाता है कि 2040 तक, तथाकथित 'जवाबी' शुल्क और प्रारंभिक प्रतिवादों का प्रभाव वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 0.7 प्रतिशत तक कम कर सकता है. मेक्सिको, चीन और थाईलैंड जैसे देशों और दक्षिणी अफ्रीका के देश भी अमेरिका के साथ-साथ सबसे अधिक प्रभावित हैं. अमेरिकी आयात पर 125 प्रतिशत शुल्क लगाने के चीन के फैसले पर, एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एएसपीआई) के वाशिंगटन डीसी स्थित कार्यालय की उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वेंडी कटलर ने कहा कि अमेरिकी आयात पर शुल्क बढ़ाने की चीन की घोषणा से यह स्पष्ट है कि यह उम्मीदें गलत हैं कि चीन इस व्यापार युद्ध में पहले कदम उठाएगा. उन्होंने कहा कि चीन को लंबी लड़ाई लड़नी है.

ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा मकानों की खरीद पर लगाई 2 वर्ष की रोक

भारतीयों को मकान खरीदने से रोका

■ **दिल्ली, न्यूज एजेंसियां.** ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने आवास की समस्या को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने भारतीयों के साथ सभी विदेशी निवेशकों के लिए मौजूदा मकानों को खरीदने पर दो साल की रोक लगा दी है. यह नियम 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगा. पहले भी विपक्ष ने ऐसा ही प्रस्ताव रखा था. यानी अब दो साल तक कोई भी विदेशी ऑस्ट्रेलिया में सेकेंड हैंड मकान नहीं खरीद पाएगा. हालांकि, उन्हें नए बन रहे मकान खरीदने की इजाजत होगी. आवास मंत्री क्लेयर ओ नील का कहना है कि यह फैसला आवास समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं है. लेकिन सरकार की आवास योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर है. सरकार विदेशी निवेशकों के जमीन जुटाने पर भी रोक लगाएगी. उन्हें एक निश्चित समय में खाली जमीन पर निर्माण करना होगा. चुनाव नजदीक हैं. इसलिए आवास नीति एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खुद को आवास समस्या को हल करने के लिए सबसे बेहतर बता रहे हैं. सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए मौजूदा मकानों की खरीद पर दो साल की रोक लगाने का फैसला किया है. यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि आवास की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सके. यह नियम अप्रैल 2025 से मार्च 2027 तक लागू रहेगा. इस दौरान विदेशी निवेशक, जैसे अंतरराष्ट्रीय छात्र और विदेशी कंपनियां बने हुए मकानों को नहीं खरीद पाएंगे. वे सिर्फ नए बन रहे मकानों में ही पैसा लगा सकते हैं. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि नए मकानों का निर्माण बढ़े. पैसिफिक वीजा योजना के तहत काम करने वाले लोग इस नियम से बाहर रहेंगे. सरकार विदेशी निवेशकों के जमीन जुटाने पर भी रोक लगाएगी. इसका मतलब है कि विदेशी निवेशकों को एक निश्चित समय के अंदर खाली जमीन पर निर्माण करना होगा.

विदेशी निवेशक कितना खरीदते हैं मकान?

द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में विदेशी खरीदारों ने 5,360 मकान खरीदे थे. इनमें से केवल एक तिहाई मकान ही पहले से बने हुए थे. प्रॉपर्टी काउंसिल के मैथ्यू कैंडेलार्स ने कहा कि विदेशी निवेश को सीमित करने से आवास की समस्या पर शायद ही कोई असर पड़े. लेकिन नए निर्माण पर फोकस एक अच्छा कदम है. कैंडेलार्स ने कहा, 'यह खुशी की बात है कि दोनों प्रमुख पार्टियों ने यह माना है कि नए मकानों का निर्माण ही आवास की समस्या को हल करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है. विपक्ष के नेता पीटर डूटन ने भी मई 2024 में ऐसा ही ऐलान किया था. उस समय ट्रेजरर जिम चामर्स ने इस प्रस्ताव को 'पागलपन' बताया था. मंत्री बिल शॉर्टेन ने कहा था कि पिछले दो वर्षों में विदेशी निवेशकों ने 5,000 से भी कम मकान खरीदे हैं. हालांकि, ओ नील ने कहा है कि उन्हें राजनीति की कोई परवाह नहीं है. वह आवास के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई अपने मकानों में रह सकें. यह बदलाव उसमें मदद करेगा. सरकार ने इस नियम को लागू करने और विदेशी निवेश की जांच को बेहतर बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टैक्सेशन ऑफिस को हर साल 14 लाख डॉलर दिए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, एटीओ और ट्रेजरी को विदेशी निवेशकों के जमीन जमा करने के खिलाफ ऑडिट और नियमों का पालन कराने के लिए 2029-30 तक हर साल 22 लाख डॉलर और उसके बाद हर साल 19 लाख डॉलर मिलेंगे.

QUICK NEWS

GSTR-3बी फॉर्म में फेरबदल नहीं

दिल्ली. जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि अप्रैल, 2025 से जीएसटी करदाताओं को मासिक कर भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में अपंजीकृत व्यक्तियों और छोटे करदाताओं (कंपोजिशन योजना के अंतर्गत आने वाले करदाता) को की गई अंतर-राज्यीय आपूर्तियां दिखाने वाली तालिका में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए तकनीकी रीढ़ की भूमिका निभाने वाले जीएसटीएन ने एक परामर्श में कहा कि अप्रैल, 2025 की कर अवधि से जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.2 में अपने-आप दर्ज अंतर-राज्यीय आपूर्तियां संपादित नहीं की जा सकेंगी.

51 लाख SIP खाते बंद

निवेशकों का भरोसा डगमगाया

■ **दिल्ली, नवभारत न्यूज नेटवर्क.** पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने से ही घरेलू शेयर बाजार में जारी जबरदस्त उतार-चढ़ाव के कारण छोटे निवेशकों का भरोसा काफी डगमगा गया है. इसका असर इक्विटी म्युचुअल फंडों में होने वाले निवेश और एसआईपी अकाउंट्स की संख्या में आई गिरावट से भी पता चलता है. मार्च के महीने में निवेशकों की बेरुखी के कारण 51 लाख एसआईपी अकाउंट्स बंद हो गए. इसी तरह मार्च के महीने में इक्विटी म्युचुअल फंडों में होने वाला निवेश भी 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड इन इंडिया (एएमएफआई) के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च के महीने में म्युचुअल फंडों में होने वाले ओवरऑल निवेश में गिरावट आई है. खासकर, इक्विटी म्युचुअल फंडों का इनफ्लो पिछले 11 महीने के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया है.

बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा प्रयास

40,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदेगा RBI

■ **दिल्ली, नवभारत न्यूज नेटवर्क.** भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वह 17 अप्रैल को अलग-अलग परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा, जिनकी कुल कीमत 40,000 करोड़ रुपये होगी. बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के मकसद से चालू वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों की यह तीसरी ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) खरीद होगी. 20,000 करोड़ रुपये की पहली खरीद 3 अप्रैल को की गई थी, जबकि इतनी ही राशि की दूसरी खरीद 8 अप्रैल को की गई थी. आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि जनवरी 2025 से अब तक रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में करीब 7 लाख करोड़ रुपये डाले हैं. लिक्विडिटी बढ़ाने के साथ ही रिजर्व बैंक ने फरवरी और अप्रैल में दो बार रेपो रेट में कटौती भी की. इसके चलते बैंक और एनबीएफसी के लोन पर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है. बता दें कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन, डॉलर-रुपया स्वैप और वेरिएबल रेपो रेट जैसे कई तरीके अपनाता है.

इस पॉलिसी के तहत आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बॉन्ड, सिक्योरिटीज जैसे सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती है या बेचती है. बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को बढ़ाने और अर्थव्यस्था को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती है, जिससे बैंक के पास पैसा आता है. बैंक अधिक कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित होंगे. इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. इसी तरह से इकोनॉमी में एक्सेस लिक्विडिटी को कम करने के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देता है, जिससे बैंकों के पास लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी और इस तरह से मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा. ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा टूल है.

'हाजमोला' कैंडी है या आयुर्वेदिक दवा

जीएसटी डिपार्टमेंट ने खोली फाइल

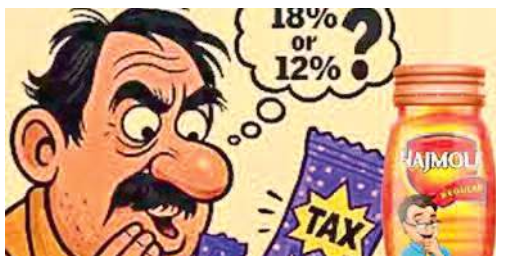

■ **दिल्ली, नवभारत न्यूज नेटवर्क.** एफएमसीजी सेक्टर की जानी मानी कंपनी डाबर जीएसटी अधिकारियों के चक्कर में फंस गई दिखती है. लोगों की पसंदीदा हाजमे की गोली हाजमोला पर टैक्स को लेकर सवाल उठाया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि यह कैंडी है जबकि डाबर कंपनी हाजमोला को आयुर्वेदिक दवा बता रही है. अगर यह कैंडी है, तो इस पर 18% टैक्स लगेगा. अगर आयुर्वेदिक दवा है, तो 12% टैक्स लगेगा.

18% के जीएसटी की डिमांड

दरअसल जीएसटी इंटेलीजेंस महानिदेशालय का कोयम्बटूर जोन इस बात की जांच कर रहा है कि यह कैंडी या आयुर्वेदिक दवा. डीजीजीआई इसे कैंडी मान रहा है और इस पर 18 फीसदी के जीएसटी की डिमांड कर रहा है. लेकिन डाबर ने इस ऑफिस को को जवाब दिया है कि हाजमोला एक आयुर्वेदिक दवा है. इसे चीनी से बनी कैंडी नहीं मानना चाहिए.

पहले भी हो चुका है विवाद

यह मामला पहले भी उठाया गया था. उस समय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हाजमोला एक आयुर्वेदिक दवा है. हाजमोला हर घर में इस्तेमाल होता है. इसे कैंडी या कंफेक्शनरी आइटम नहीं मानना चाहिए. डाबर कंपनी को इनकम टैक्स का एक नोटिस भी मिला है.

1 अप्रैल को डाबर ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 110.33 करोड़ रुपये का टैक्स भरने का आदेश दिया है. इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि डाबर ने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 14ए के तहत टैक्स में गलत छूट का दावा किया है. मतलब डाबर ने टैक्स बचाने के लिए कुछ गलत तरीके अपनाए, ऐसा इनकम टैक्स विभाग का मानना है.

बाजार में उतार-चढ़ाव, मल्टी एसेट फंड बेहतर विकल्प

13.7% तक का वार्षिक रिटर्न

■ **मुंबई, नवभारत न्यूज नेटवर्क.** यदि आपको लगता है कि कुछ महीने पहले इक्विटी में निवेश करना ही सबसे सही जगह है, तो आपने अपने निवेश को दोगुना कर दिया और अब घाटे में हैं, तो आप अकेले नहीं हैं. इन्वेस्ट इंडिया फाइनेंशियल के निदेशक कौशिक भट्ट का कहना है कि ऐसी कठिन हालात में ही विशेषज्ञ यानी फंड मैनेजर का महत्व समझ में आता है. फंड मैनेजर भावनाओं के बजाय बुनियादी बातों के आधार पर निवेश करता है. वे निष्पक्ष, शोध-समर्थित, सही समय पर खरीद और बिक्री के फैसले लेकर न केवल जोखिम कवर करते है बल्कि उचित रिटर्न भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. मौजूदा अस्थिर माहौल में मल्टी एसेट या एसेट एलोकेशन फंड सही हैं. ये फंड इक्विटी, डेब्ट और गोल्ड में संतुलित रूप से निवेश कर कमाई करते हैं. एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी में निवेशक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं. 28 फरवरी, 2025 तक, इसने एक साल में 7% रिटर्न दिया है तथा तीन वर्ष में सालाना 11.80% और पांच वर्ष में 13.7% का सालाना रिटर्न प्रदान किया है.

सामान 1,000 का हो या 10,000 का पेमेंट कर रहे कार्ड से

लोगों को लग रही है क्रेडिट कार्ड की लत

■ **दिल्ली, न्यूज एजेंसियां.** वर्ष 2024 में सभी घरेलू डिजिटल भुगतान लेनदेन में से करीब एक-तिहाई लेनदेन क्रेडिट कार्ड या ब्याज वाली मासिक किस्तों के जरिये किए गए थे. डिजिटल भुगतान क्षेत्र की कंपनी फाई कॉमर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल भुगतान में यूपीआई एक परिवर्तनकारी उत्पाद बनकर उभरा है और कुल लेनदेन में इसकी हिस्सेदारी 65 प्रतिशत हो चुकी है. रिपोर्ट कहती है कि छोटे और मध्यम मूल्य वाले लेनदेन पर यूपीआई हावी है जबकि क्रेडिट कार्ड और ईएमआई (समान मासिक किस्त) का उपयोग बड़ी खरीदारी के लिए तेजी से किया जा रहा है. इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वाहन सहायक क्षेत्रों में डिजिटल ऋण लेने की दर में मजबूत वृद्धि देखी गई है. त्योहारी खरीदारी, स्कूल में दाखिले और मौसमी रुझान क्रेडिट के इस्तेमाल में तेजी लाते हैं. इससे पता चलता है कि उपभोक्ता अधिक खर्च वाले समय में अल्पकालिक ऋण सुविधा का सहारा लेना पसंद करते हैं.

यह रिपोर्ट देश भर के 20,000 से अधिक दुकानदारों से ऑनलाइन भुगतान के बारे में जुटाए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है. फाई कॉमर्स के सह-संस्थापक राजेश लोंढे ने कहा कि यूपीआई और लचीले ऋण विकल्पों का इस्तेमाल आम होते जाने के साथ भविष्य उन लोगों का है जो समावेशी विकास और वित्तीय मजबूती को बढ़ावा देने के लिए इन साधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं. मौजूदा समय में उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करने के बजाय अपने खर्च को वित्तपोषित करना पसंद करते हैं. यह खासकर शिक्षा (10 प्रतिशत), स्वास्थ्य सेवा (15 प्रतिशत) और वाहन सहायक व्यय (15 प्रतिशत) में स्पष्ट है, जहां बड़ी खरीदारी तेजी से ईएमआई और संरचित क्रेडिट विकल्पों के जरिये की जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल की फीस, इलाज पर खर्च और बड़ी ऑनलाइन खरीद के लिए ईएमआई योजनाओं पर निर्भरता ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार में बदलाव को दर्शाती है. अब वे चरणबद्ध ढंग से खर्च और उसके प्रबंधन पर ध्यान देते हैं.

MSME और महिला उद्यमियों में लोन की बढ़ रही मांग

इंडेल मनी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक व सीईओ उमेश मोहनन की 'नवभारत' से बातचीत

सरकार एमएसएमई और महिला उद्यमियों के लिए क्रेडिट एक्सेस पर ध्यान दे रही है. इंडेल मनी अपनी ऑफरिंग में इस प्राथमिकता को कैसे शामिल कर रही है?

एमएसएमई और महिला उद्यमियों को फॉर्मल क्रेडिट यानी आसान कर्ज उपलब्ध कराने की सरकार की पहल के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं. हाल में मुद्रा लोन के जो आंकड़े आए हैं और वे काफी हद तक सकारात्मक तस्वीर पेश कर रहे हैं. पिछले 10 साल में स्वीकृत कुल राशि में महिलाओं और पहली बार कारोबार करने वाले उद्यमियों की हिस्सेदारी क्रमशः 44 प्रतिशत और 31 प्रतिशत है. हालांकि, इस सेगमेंट में लोन की डिमांड काफी अधिक है और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अकेले उनकी मांग पूरी नहीं कर सकते हैं. निश्चित रूप से गोल्ड लोन एनबीएफसी की इस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपस्थिति रहने वाली है क्योंकि गोल्ड लोन झंझट रहित ब्रिज लोन या शॉर्ट-टर्म वर्किंग कैपिटल लोन की तरह काम करेगा. इन सेगमेंट में हमारी उपस्थिति काफी अच्छी है और पिछले एक दशक से हम उन्हें बेहतर तरीके से सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं.

सोने की कीमतों में तेजी के कारण गोल्ड लोन की मांग पर क्या असर है? क्या ग्राहक ज्यादा लोन ले रहे हैं या तेजी से लोन चुका रहे हैं?

गोल्ड लोन की मांग काफी अधिक बढ़ी है क्योंकि कीमतों में उछाल की वजह से बॉरोअर्स के हाथ में ज्यादा रकम आती है. इसके अलावा, यह बिना किसी झंझट के तुरंत मिलने वाला लोन है, जिससे किसी भी तरह की वित्तीय जरूरत तत्काल पूरी की जा सकती है. सोने के दाम बढ़ने पर अधिकतर लोग टॉप-अप लोन लेते हैं.

इंडेल मनी को आगे किन क्षेत्रों में ग्रोथ तेज होने की उम्मीद है? क्या अन्य इलाकों में विस्तार का प्लान है?

इंडेल मनी उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में तेजी से विस्तार कर रही है, जहां असंगठित गोल्ड लोन कंपनियों की काफी कम या नाममात्र की मौजूदगी है. इन क्षेत्रों में असंगठित कंपनियों का ज्यादा दबदबा है. हम इसे भुनाना चाहते हैं. हमारे लिए नए भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. हालांकि, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की राह में रेगुलेटरी बाधाएं देखने को मिल सकती हैं. इसलिए मौजूदा समय में हम ब्रांच नेटवर्क के विस्तार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

INDEL MONEY

गोल्ड लोन की भी बढ़ रही डिमांड

क्या इंडेल मनी की पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय वित्तीय संस्थाओं या एनबीएफसी के साथ साझेदारी करने की कोई योजना है?

हां, अच्छी एवं प्रभावी स्थानीय कंपनियों के साथ हमारा पहले से ही को-लेंडिंग समझौता और अन्य गठजोड़ है. इससे हमें सुदूर इलाकों और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिलेगी, जहां अब तक बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंची हैं.

इस साल ब्याज दरों में कमी को लेकर आरबीआई से आपको किस तरह की उम्मीदें हैं? आप आरबीआई एमपीसी के फैसलों का गोल्ड लोन सेक्टर पर किस तरह का असर देखते हैं?

आरबीआई एमपीसी की आगामी बैठकों में भी ब्याज दरों में और कमी की जा सकती है क्योंकि इकोनॉमी कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है, खासकर वैश्विक कारणों की वजह से. इसलिए इस पूरे वित्त वर्ष में आरबीआई ब्याज दरों में कमी कर सकता है और पूंजी डालना जारी रख सकता है, लेकिन इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल है कि ब्याज दरों में कितनी ढील दी जाएगी क्योंकि वैश्विक परिदृश्य काफी पेचीदा और अस्थिर स्थिति में है.

आरबीआई द्वारा गोल्ड लोन नियमों में बदलाव पर आपकी क्या राय है?

महत्वपूर्ण बात यह है कि गोल्ड लोन से जुड़े रेगुलेशन को सुसंगत बनाने या मानकीकृत करने का आरबीआई का हालिया फैसला गोल्ड लोन एनबीएफसी के लिए फायदेमंद है. वर्तमान में, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. एनबीएफसी, बैंकों की तुलना में हमेशा नुकसान की स्थिति में थे क्योंकि लेंडर्स को सस्ते में फंड मिल जाता है, वे गोल्ड-आधारित एग्री लोन दे सकते हैं, वे हाई लोन-टू-वैल्यू रेशियो की पेशकश कर सकते हैं, और उन्हें अनुकूल रिन्यूएबल पॉलिसीज का फायदा मिलता है. सेंट्रल बैंक के इस नए फैसले के बाद स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा और यह एक स्वागत योग्य कदम है.

पूर्व रेलवे

ई-निविदा सूचना सं.: डब्ल्यू_एलएलएच_01_2025-26, दिनांक 09.04.2025; उप मुख्य यांत्रिक अभियंता/विद्युत, सीएंडडब्ल्यू वर्कशॉप, पूर्व रेलवे, लिलुआ, हावड़ा-711204 द्वारा नीचे उल्लेखित कार्य के निष्पादन के लिए तकनीकी रूप से सक्षम निविदादाताओं से ऑनलाइन ई-निविदाएं (खुली निविदा) आमंत्रित की जाती हैं: **कार्य का नामः** सीएंडडब्ल्यू वर्कशॉप, पूर्व रेलवे, लिलुआ में आईसीएफ एवं एलएचबी टाइप नॉन-एसी कोचों की विद्युतीय सामग्रियों की स्ट्रिपिंग, स्थानातंरण, स्क्रबिंग, धूल निकालना, सफाई, फिटमेंट, पेंटिंग एवं अन्य आनुषंगिक कार्य। **कार्य की अनुमानित लागतः** रु. 1,50,84,324.32; **बयाना राशिः** रु. 2,25,400; **निविदा बंद होने की तारीख एवं समयः** 02.05.2025 को अपराह्न 2.00 बजे। **वेबसाइट जहां निविदा का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध हैः www.ireps.gov.in**

(MISC-13/2025-26)

निविदा सूचनाएं वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें अनुसरण करें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पश्चिम रेलवे

रेलवे जमीन की सुरक्षा हेतु प्रस्तावित बाड़ का निर्माण

वरि. डीईएन (दक्षिण) एमएमसीटी, मुंबई सेंट्रल - मुंबई-400008 द्वारा **निविदा सूचना क्र. : बीसीटी/25-26/12, दिनांक : 08.04.2025** आमंत्रित की जाती है. **कार्य एवं स्थान : चर्चगेट-विरार अनुभाग :** बाहरी तत्वों/झुग्गीधारकों द्वारा कचरा फेंके जाने से सुरक्षा के लिए बाड़ का प्रस्तावित निर्माण. **कार्य की अनुमानित लागत :** ₹ 46,66,702.44. **ईएमडी :** ₹ 93,300/-. **जमा करने की तिथि एवं समय :** 02.05.2025, 15.00 बजे तक. **खुलने की तिथि एवं समय :** 02.05.2025 को 15.30 बजे. अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.ireps.gov.in** का अवलोकन करें. 0030

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

मध्य रेल

मुंबई मंडल

ओएचई बांड की आपूर्ति और निर्माण

कार्य का विवरण :– मुंबई मंडल के कल्याण और लोनावाला जिलों में विभिन्न टीटीआर, टीएसआर, टीआरआर और टीबीआर कार्यों के संबंध में ओएचई बांड की आपूर्ति और निर्माण। **अनुमानित लागत** : रु. 3449807.36/-, **ईएमडी** : रु. 69000.00/-, **निविदा प्रपत्र का शुल्क** : रु. 0.00/-, **समापन अवधी** : 12 महिने, ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथी एवं अवधि दि. 13.05.2025 को 11:00 बजे है। ई-निविदा की विस्तृत जानकारी रेल की अधिकारीक वेबसाइट : https://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा की जानकारी वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क.वि.) मध्य रेल, कल्याण के सुचना पट पर उपलब्ध है।

खुली ई-निविदा संख्या :

केवायएन-एलडी-585-डब्लु-745-कांट

दि. 09.04.2025 **व.मं.वि.इं. (क.वि.)**

SUN 24 **मध्य रेल, कल्याण**

टिकट के लिए UTS APP डाउनलोड करें

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा मेरे मुवक्किल के निर्देशानुसार, मैं **1. श्री विष्णु परसाराम काबरा और 2. श्रीमती आशा विष्णु काबरा,** जो यहां निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित फ्लैट संपत्ति के मालिक हैं, के संबंध में, के शीर्षक की जांच कर रहा हूं. कोई भी व्यक्ति जिनका अनुसूचित संपत्ति अथवा उसके किसी भी भाग में पट्टा, उपहार, ग्रहणाधिकार, गिरवी, लाइसेंस, प्रभार, विनिमय, बिक्री अथवा अन्यथा किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकार, शीर्षक, अभिरूचि तथा/अथवा दावा है तो उनसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को जी-5, मुकुट, बी विंग, 20-बी, एस.वी. रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई - 400 050 स्थित कार्यालय पते पर समर्थनीय दस्तावेजी प्रमाणों के साथ लिखित में अपने दावे की जानकारी दें अन्यथा ऐसे किसी भी दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा अथवा उन्हें छोड़ा हुआ अथवा त्यागा हुआ मान लिया जाएगा.

उपरोक्त संदर्भित अनुसूची :

शेयर प्रमाणपत्र क्र. 137 तथा विशिष्ट क्र. 711 से 715 (दोनों समाविष्ट) धारक मैराथन एरा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. के प्रत्येक रुपए 100/= के 5 पूर्णतः अदा किए गए शेयर्स के साथ वीर संताजी मार्ग, ऑफ गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013 स्थित एवं मौजूद लोअर परेल डिवीजन की कैडस्ट्रल सर्वे क्र. 2/142 धारक जमीन पर निर्मित **"मैराथन नेक्स्ट जन एरा, ईआरए-III"** नामक बिल्डिंग में 1143 वर्ग फीट कारपेट एरिया धारक, 18वीं मंजिल पर फ्लैट क्र. 1801.

दिनांक : 12 अप्रैल 2025

हस्ता./-

(शब्बीर एस. कपाडिया)

एडवोकेट एवं सॉलिसिटर

पश्चिम रेलवे

ओएचई के सिंगल स्पैन ओवरलैप का थ्री स्पैन ओवरलैप में रूपांतरण

वरि. मंडल विद्युत अभियंता (सब.), पश्चिम रेलवे, मुंबई सेंट्रल द्वारा **ई-निविदा क्र. : डब्ल्यूआर-एमएमसीटीओईएसयूबी (ईएसओटी)/ 11/2024, दि. : 08.04.2025** आमंत्रित की जाती है. **कार्य का नाम : चर्चगेट-विरार अनुभाग :** ओएचई के सिंगल स्पैन ओवरलैप का थ्री स्पैन ओवरलैप में रूपांतरण. **कार्य की अनुमानित लागत :** ₹ 9,71,70,438/-, **बोली सुरक्षा :** ₹ 6,35,900/-. **जमा करने की तिथि एवं समय :** 06.05.2025, 15.00 बजे तक. **खुलने की तिथि एवं समय :** 06.05.2025 को 15.30 बजे. अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.ireps.gov.in** का अवलोकन करें. 0031

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

अनरेग्युलेटेड ओएचई का रूपांतरण

वरि. मंडल विद्युत अभियंता (सब.), पश्चिम रेलवे, मुंबई सेंट्रल द्वारा **ई-निविदा क्र. : डब्ल्यूआर-एमएमसीटीओईएसयूबी (ईएसओटी)/ 10/2024, दि. : 08.04.2025** आमंत्रित की जाती है. **कार्य का नाम : अंधेरी-बोरीवली अनुभाग :** यूपीटीएच और डीएनटीएच लाइंस के अनरेग्युलेटेड ओएचई का रेग्युलेटेड ओएचई में रूपांतरण. **कार्य की अनुमानित लागत :** ₹ 12,01